[2010] 11 एस. सी. आर 1123

पंजाब एंड सिंड बैंक

बनाम

मेसर्स एलाइड बेवरेज कंपनी पी. प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(2010 की सिविल अपील सं. 8443)

1 अक्टूबर, 2010

[पी. सतशिवम और डॉ. बी. एस. चौहान, जे. जे.]

रुचिः ब्याज की दर- बैंक द्वारा किसी कंपनी को दी गई नकद ऋण सुविधा- कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा- बैंक में उसके खाते को गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया- वसूली मुकदमा- डी. आर. टी. ने कंपनी को मासिक विश्राम के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया- उच्च न्यायालय ने लंबित राशि और भविष्य मुकदमेबाजी का इंतजार को 12 मासिक विश्राम के साथ घटाकर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष करके डी. आर. टी. के आदेश को संशोधित किया- आयोजितःउच्च न्यायालय ने बैंक के दावे के साथ- साथ कंपनी की पीड़ाओं को काफी हद तक बेअसर आदेश दिया और ब्याज की दर को

घटाआदेश 14 प्रतिशत प्रति वर्ष आदेश दिया जो कि सरल ब्याज होगा- उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम स्वीकार्य- बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली- धारा 19 (20)- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949- धारा 21A- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- एस. 34 अपीलार्थी- बैंक ने प्रत्यर्थी कंपनी को कंपनी की परिसंपत्तियों के अनुमान के माध्यम से विधिवत सुरक्षित नकद ऋण सुविधा प्रदान की। कंपनी को अपने व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ा और बैंक में उसके खाते को गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में घोषित कर दिया गया। बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कंपनी के निदेशकों को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें बकाया राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा गया। कंपनी ने खातों के निपटान के लिए बैंक से संपर्क किया। हालांकि, थोड़ा और भविष्य का हित। डी. आर. टी. ने आवेदन की अनुमति दी। डी. आर. ए. टी. ने डी. आर. टी. के निर्णय को बरकरार रखा। कंपनी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने डी. आर. टी. द्वारा दिए गए मासिक विश्राम के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज की तुलना में लंबित राशि और भविष्य मुकदमेबाजी का इंतजार डब्ल्यू. ई. एफ. 04.07.2003 को मासिक विश्राम के साथ घटाआदेश 14 प्रतिशत प्रति वर्ष आदेश दिया। बैंक ने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली की खंड 19 (20), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की खंड 21ए और सी. पी. सी. की खंड 34 के प्रावधान मुकदमेबाजी का इंतजार की दर या मात्रा पर विचार करते समय प्रासंगिक हैं। तत्काल मामले में, कंपनी समझौते के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों और अन्य सभी परिस्थितियों के कारण यह सफल नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय ने बैंक के दावे के साथ- साथ कंपनी की पीड़ाओं को काफी हद तक बेअसर आदेश दिया और ब्याज की दर को घटाआदेश 14 प्रतिशत प्रति वर्ष आदेश दिया, जो कि साधारण ब्याज होगा, अवधि के लंबित और भविष्य मुकदमेबाजी का इंतजार के संबंध में। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम स्वीकार्य है और बैंक द्वारा दावा किए गए ब्याज की दर को बढ़ाने या कंपनी द्वारा अनुरोध किए जाने पर इसे और कम करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। [पैरा 9,13,14) [1129- जी; 1137- एफ- जी; 1138- ए]

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र और अन्य (2002) 1 धारा 367- पर निर्भर था।

एन. एम. वीरप्पा बनाम केनरा बैंक (1998) 2 एस. सी. सी. 317; सिंडिकेट बैंक, चेन्नई अन्य मोहन ब्रदर्स और अन्य। (2004) 10 धारा 549- निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भः

(2002) 1 धारा 367 पैरा 11 पर निर्भर थी।

(1998) 2 धारा 311 पैरा 10 को संदर्भित करती है।

(2004) 10 धारा 549 पैरा 13 को संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के 2007 की सिविल रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 6069 में दिनांकित 24.08.2007 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2010 का सीए सं सं. 8444

उपस्थित दलों के लिए राजीव दत्ता, कुमार दुष्यंत सिंह, आर. नेदुमारन, दीपक भट्टाचार्य, राजेश कुमार, प्रियंका कुमारी, सतीश अग्रवाल, गुरबीर सिंह रायखी, सूर्यकांत।

न्यायालय का निर्णय पी. सतशिवम, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अवकाश अनुदत्त गई।

2. ये अपीलें नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2007 की रिट याचिका (सी) सं. 6069 में पारित किए गए निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने मेसर्स मुकदमेबाजी का इंतजार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण- II, दिल्ली (इसके बाद "डीआरटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा 2003 के मूल आवेदन संख्या 47 में पारित आदेश को संशोधित किया गया था।

3. संक्षिप्त तथ्यः

(क) आई. डी. 1 दिनांकित आवेदन के माध्यम से, कंपनी ने बैंक से संपर्क किया और अपने नाम पर वित्तीय सुविधाओं के अनुदान के लिए अनुरोध किया। कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद, बैंक ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और रुपये 60,00,000/- रुपये 20,00,000/- का सावधि ऋण, रुपये 10,00,000/- की एफओबीएलसी/एफओबीपी सुविधा और रुपये 25,00,000/- की सीमा तक आयात/अंतर्देशीय ऋण पत्र सुविधा प्रदान की। हालांकि, नकद ऋण और आयात/अंतर्देशीय ऋण पत्र की सीमा रुपये 60,00,000/- से अधिक नहीं थी। बैंक द्वारा दी गई उपरोक्त ऋण सुविधाओं को कच्चे माल, तैयार उत्पादों, पारगमन और प्रक्रिया में वस्तुओं, तैयार वस्तुओं, जनरेटर सेट

और टैंकों के स्टॉक पर परिकल्पना के माध्यम से विधिवत सुरक्षित किया गया था, जिन पर हरियाणा वित्तीय निगम (जिसे इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पहला शुल्क लगाया गया है और उपरोक्त सभी सामग्रियों पर बैंक का दूसरा शुल्क था। इसके अतिरिक्त, उक्त ऋण सुविधाओं को प्लॉट संख्या 9, रोड ई संख्या वाली अचल संपत्ति के संबंध में मूल स्वामित्व विलेखों को जमा करके न्यायसंगत बंधक के माध्यम से भी सुरक्षित किया गया था। डब्ल्यू- 8, डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव, फेज- II, गाँव नाथुरपुर, तहसील और जिला। गुड़गांव का माप लगभग 450.78 वर्ग मीटर है। एमटीएस। श्री सुरिंदर कुमार साधु- कंपनी के निदेशक। 16.07.1997 पर, बैंक ने कंपनी को उपरोक्त ऋण/ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी और प्रदान किया। कंपनी ने बैंक के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए। कुछ कारणों से, कंपनी के व्यवसाय को एक झटका लगा और बैंक के साथ इसके खाते को 31.03.1999 पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन पी ए) के रूप में घोषित किया गया। उस तारीख तक, कैश क्रेडिट खाते में रुपये 60,99,482.77- और टर्म लोन खाते के संबंध में रुपये 15,05,470/- की राशि देय थी। कंपनी के खाते को 01.04.1999 पर एन. पी. ए. खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(बी) 16.09.2002 पर, बैंक ने अपने प्रबंधक द्वारा से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'प्रतिभूतिकरण अधिनियम') के प्रवर्तन के

तहत कंपनी के निदेशकों को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें देय ब्याज के साथ बैंक को देय बकाया का भुगतान करके खाते को नियमित करने के लिए कहा गया और कहा गया कि ऐसा न करने पर बैंक उनके खिलाफ प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। नोटिस मिलने पर, कंपनी ने खातों के निपटारे के लिए बैंक से संपर्क किया और लिखित में एक प्रस्ताव दिया और टोकन राशि के लिए रुपये की राशि भी जमा की। हालाँकि, निपटान को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि यह सी के निचले हिस्से में था और इस तरह टोकन राशि कंपनी के खाते में जमा की गई थी।

(ग) 04.07.2003 पर, बैंक ने डी. आर. टी. के समक्ष 2003 का ओ. ए. संख्या 47 होने के कारण लंबित राशि और भविष्य मुकदमेबाजी का इंतजार के साथ रु. 1,47,42,616.77 की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन विचाराधीनता रहने के दौरान, कंपनी ने आगे निपटान के लिए एक प्रस्ताव दिया लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा सका। हालाँकि, 09.06.2005 पर, पीठासीन अधिकारी ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और कंपनी को बकाया राशि का भुगतान लटकती राशि और भविष्य मुकदमेबाजी का इंतजार के साथ करने का निर्देश दिया। पीठासीन अधिकारी ने आगे निर्देश दिया कि एक वसूली प्रमाण पत्र तैयार किया जाए और उसमें पक्षकारों को इसे निष्पादित करने के लिए रिकवरी अधिकारी- I, डी. आर. टी.- 111 दिल्ली के समक्ष 09.08.2005 पर उपस्थित होना

चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, कंपनी ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद 'ओ. आर. ए. टी.' के रूप में संदर्भित किया गया है), दिल्ली के समक्ष 2006 की अपील संख्या 70 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी और इसे दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

(घ) डी. आर. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 29.03.2007 के आदेश को चुनौती देते हुए, कंपनी ने 10.07.2007 पर उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 की रिट याचिका (सी) संख्या 6069 को प्राथमिकता दी। दिनांक 24.08.2007 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने ब्याज के संबंध में आदेश को उसमें उल्लिखित सीमा तक संशोधित करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट, बैंक ने 2007 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 24745 से उत्पन्न अपील दायर की और कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष 2008 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 3373 से उत्पन्न अपील को प्राथमिकता दी।

4. बैंक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील के साथ- साथ कंपनी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील को सुना।

5. विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते है:

(i) क्या उच्च न्यायालय संविदात्मक ब्याज दर की सराहना किए बिना 12 मासिक विश्राम के साथ मासिक विश्राम के साथ ब्याज को 18

प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से घटाकर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष करना उचित है।

(ii) क्या उच्च न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) की खंड 34 के तहत ब्याज के भुगतान की आवधिकता को बदलने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, जिसमें डी. आर. टी. द्वारा पारित मूल निर्णय और डिक्री के अनुसार, ब्याज मासिक विश्राम के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष देय था, जबकि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 12 मासिक विश्राम के साथ ब्याज की दर को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया है।

(ग) क्या प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज दर में और कमी के लिए कंपनी का दावा व्यवहार्य और स्वीकार्य है।

6. चूंकि हम केवल इन अपीलों में ब्याज की दर से संबंधित हैं, इसलिए उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए सभी तथ्यात्मक विवरणों को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय कुछ तथ्यों के जिन्हें हमने पहले के पैराग्राफ में जोड़ा है।

7. ब्याज के संबंध में बैंक के साथ- साथ कंपनी के दावे की सराहना आदेशने के लिए, प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित आदेशना उपयोगी है जो मामले में लागू होते हैं। बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के

कारण ऋणों की वसूली का अध्याय IV न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित है। विभिन्न प्रावधानों में, हम खंड 19 के बारे में चिंतित हैं।

(20) जो नीचे लिखा हैः

"19. न्यायाधिकरण में आवेदनः-

(20) न्यायाधिकरण, आवेदक को देने के बाद और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर, ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करना, जिसमें उस तारीख से ब्याज के भुगतान का आदेश शामिल है, जिस तारीख को या उससे पहले राशि का भुगतान प्राप्त होने या वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय पाया जाता है, आवेदन पर जो वह न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित समझता है।"

8. बैंकिंग कंपनियों को विनियमित आदेशने के लिए, भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 नामक कानून बनाया। यहाँ फिर से, हम ब्याज दर से संबंधित प्रावधान के बारे में चिंतित हैं जो प्रदान किया गया है।

खंड 21ए जो इस प्रकार हैः

"21. बैंकिंग कंपनियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों की अदालतों द्वारा जांच नहीं की जानी चाहिए। ब्याज ऋण अधिनियम, 1918 (1918 का 10) या किसी भी राज्य में

लागू ऋण से संबंधित किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी बैंकिंग कंपनी और उसके देनदार के बीच लेनदेन को किसी भी अदालत द्वारा इस आधार पर फिर से नहीं खोला जाएगा कि ऐसे लेनदेन के संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा ली गई ब्याज की दर अत्यधिक है।"

9. उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अलावा, खंड 34 सी. पी. सी. मुकदमेबाजी का इंतजार की दर या मात्रा पर विचार करते समय और डिक्री पारित करने के बाद भी प्रासंगिक है। वह इस प्रकार हैः

"34. रुचि है। - (1) जहां और जहां तक कोई डिक्री धन के भुगतान के लिए है, वहां न्यायालय डिक्री में ऐसी दर पर ब्याज का आदेश दे सकता है जो न्यायालय निर्णय की गई मूल राशि पर, मुकदमा की तारीख से डिक्री की तारीख तक, मुकदमा की स्थापना से पहले की किसी भी अवधि के लिए ऐसी मूल राशि पर निर्णय किए गए किसी भी ब्याज के अलावा, ऐसी मूल राशि पर ऐसी दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ छह प्रतिशत से अधिक नहीं, प्रति वर्ष, जो न्यायालय डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक, या ऐसी पूर्व तिथि तक, जो न्यायालय उचित समझे, देः

बशर्ते कि जहां इस प्रकार निर्धारित राशि के संबंध में देयता एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुई थी, वहां इस तरह के अतिरिक्त ब्याज की दर प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक हो सकती है, लेकिन ब्याज की संविदात्मक दर से अधिक नहीं होगी या जहां कोई संविदात्मक दर नहीं है, वह दर जिस पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में धन उधार दिया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है।

स्पष्टीकरण 1.- इस उप- धारा में, "राष्ट्रीयकृत बैंक" का अर्थ है बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) में परिभाषित एक संबंधित नया बैंक।

स्पष्टीकरण 11.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक लेन-देन एक वाणिज्यिक लेन- देन है, यदि यह दायित्व वहन करने वाले पक्ष के उद्योग, व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा है।

(2) जहां ऐसी डिक्री डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख या अन्य पूर्व तिथि तक ऐसी मूल राशि पर आगे के ब्याज के भुगतान के संबंध में मौन है, तो यह माना जाएगा कि न्यायालय ने ऐसे ब्याज को अस्वीकार कर दिया है और इसके लिए एक अलग मुकदमा नहीं होगा।"

10. एन. एम. वीरप्पा बनाम। केनरा बैंक, (1998) 2 एस. सी. सी. 317 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1101, इस न्यायालय ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की खंड 21ए पर विचार करते हुए, जिसे 1984 के अधिनियम 1 द्वारा पेश किया गया था, डब्ल्यू. ई. एफ. 15.02.1984 ने पैरा 23 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> "..... सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाएगा कि खंड 21- ए में "गैर- एक बाधा खंड" का प्रभाव केंद्रीय अधिनियम, अर्थात् ब्याज ऋण अधिनियम, 1918 और किसी भी राज्य में लागू ऋण से संबंधित किसी भी अन्य कानून को ओवरराइड करता है। स्पष्ट रूप से यह केंद्रीय कानूनों के बीच सिविल प्रक्रिया संहिता को ओवरराइड करने का स्पष्ट रूप से इरादा नहीं रखता है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि गैर- अबाधित खंड का दायरा और चौड़ाई इस आधार पर तय की जानी है कि प्रावधान के अधिनियमन भाग में क्या निहित है। अश्विनी कुमार घोष बनाम अरबिंद बोस। इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को किसी भी राज्य में लागू ऋण से संबंधित कानून के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जहां तक केंद्रीय विधान का संबंध है, खंड 21- ए का प्रावधान केवल ब्याज ऋण अधिनियम को संदर्भित करता

है। 1918 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के लिए नहीं और फिर यह किसी भी राज्य में लागू ऋण से संबंधित अन्य कानूनों को संदर्भित करता है। इसलिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1984 की खंड 21- ए के प्रावधान का उद्देश्य सी. पी. सी. या आदेश 34 नियम 11 सी. पी. सी. जैसे केंद्रीय कानून को ओवरराइड करना नहीं माना जा सकता है।" (जोर दिया गया)

11. बैंक के साथ- साथ कंपनी और यहां तक कि उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र और अन्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 367 में संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित अनुपात पर बहुत अधिक भरोसा किया। संविधान पीठ के समक्ष प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (66/1956) डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1957 द्वारा संशोधित खंड 34 सी. पी. सी. में आने वाले वाक्यांशों "मूल राशि का निर्णय" और "ऐसी मूल राशि" के अर्थ के बारे में था।

12. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, संविधान पीठ ने "ब्याज", "दंडात्मक ब्याज", कई "ब्याज कानूनों" पर भी विचार किया है और अंत में कुछ टिप्पणियां की हैं जो बैंकिंग संस्थानों के साथ- साथ उनके साथ धन लेनदेन से निपटने वाले अन्य सभी लोगों के लिए बाध्यकारी हैं।

"ब्याज और उसके वर्ग

37. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण) "ब्याज" को अन्य बातों के साथ साथ साथ- साथ समझौते द्वारा निर्धारित या धन के उपयोग या निरोध के लिए कानून द्वारा अनुमत मुआवजे के रूप में परिभाषित करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धन के नुकसान के लिए जो इसके उपयोग का हकदार है; विशेष रूप से, उधार ली गई राशि के उपयोग के बदले में ऋणदाता को देय राशि। स्ट्राउड के जुडिशल डिक्शनरी ऑफ वड्र्स एंड फ्रेज़ेस (5 वीं संस्करण) के अनुसार, ब्याज का अर्थ है, अन्य बातों के साथ साथ साथ- साथ, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को अपने धन के उपयोग से वंचित करने के लिए भुगतान किया गया मुआवजा। सिकरी में। सिंचाई विभाग। उड़ीसा सरकार बनाम जी. सी. रॉय की संविधान पीठ ने राय दी कि धन के उपयोग से वंचित व्यक्ति, जिसका वह वैध रूप से हकदार है, को वंचितता के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है, इसे किसी भी नाम से कहें। इसे ब्याज, क्षतिपूर्ति कहा जा सकता है या उसको खंडित सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 का सिद्धांत है। शाम लाल नरूला (डॉ.) बनाम सी. आई. टी. मामले में इस न्यायालय ने कहा कि ब्याज का भुगतान धन के उपयोग से वंचित करने के लिए किया जाता है। रिचेस बनाम वेस्टमिंस्टर बैंक लिमिटेड में लॉर्ड राइट की राय में रुचि का सार। 472 यह है कि यह एक ऐसा भुगतान है जो देय हो जाता है क्योंकि लेनदार के पास नियत तिथि पर उसका पैसा नहीं होता है। इसे या तो उस लाभ का प्रतिनिधित्व

करने के रूप में माना जा सकता है जो उसने अर्जित किया होगा यदि उसने पैसे का उपयोग किया होता, या इसके विपरीत, वह नुकसान जो उसे हुआ क्योंकि उसका वह उपयोग नहीं था। सामान्य विचार यह है कि वह अभाव के लिए मुआवजे का हकदार है; लेनदार को देय धन का भुगतान नहीं किया गया था, या, दूसरे शब्दों में, देनदार द्वारा अपने अधिनियमी अधिकारों के भंग में भुगतान किए जाने के समय के बाद उससे रोक दिया गया था; और ब्याज एक मुआवजा था कि क्या मुआवजे को किसी समझौते या क़ानून के तहत समाप्त कर दिया गया था। पंजाब उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने सी. आई. टी. बनाम डॉ. शाम लाल नरूला में टेक चंद, जे. द्वारा से बोलते हुए इस प्रकार रुचि की अवधारणा को स्पष्ट कियाः(एयर पी। 414, सामान्य रूप से जनता के हित में और बैंकिंग मामलों को बिगड़ने और पूर्वाग्रह से रोकने के साथ- साथ आम तौर पर किसी भी बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए वैधानिक बल रखने वाले निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक देश के वित्त और अर्थव्यवस्था के निगरानीकर्ताओं में से एक है। यह सभी प्रासंगिक कारकों से अवगत है और उसे होना चाहिए, जिसमें प्रचलित ऋण की शर्तें भी शामिल हैं, जो इसके नीतिगत निर्णयों को आमंत्रित करेंगी। आर. बी. आई. समय- समय पर निर्देश/परिपत्र जारी करता रहा है जो अन्य बातों के साथ साथ साथ- साथ ब्याज की दर से संबंधित है जो ली जा सकती है और जिसके अंत में शेष अवधि को कम किया जा सकता है, उस पर ब्याज की

गणना की जा सकती है और शुल्क लिया जा सकता है और पूंजीकृत किया जा सकता है। इसे इस तरह के निर्देश जारी करते रहना चाहिए। इसके परिपत्र उन लोगों को बाध्य करेंगे जो इस तरह के निर्देशों के दायरे में आते हैं। ऐसे लेन- देन के लिए जो इस तरह के परिपत्रों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों को यह तय करने के उद्देश्य से मानकों के रूप में माना जा सकता है कि क्या लगाया गया ब्याज अत्यधिक है, सूदखोर है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

(6) कृषि ऋणों को दूसरों से अलग आधार पर माना जाना चाहिए। भारत में कृषि ऋणों पर ब्याज वसूलने और पूंजीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, सिवाय वार्षिक या छह- मासिक विश्राम के, जो उस क्षेत्र में फसलों के आवर्तन पर निर्भर करता है जिसमें कृषक ऋणकर्ता संबंधित हैं।

(7) आर. बी. आई. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रभारित और/या पूंजीकृत किसी भी ब्याज को, ब्याज की दर के रूप में, या उस अवधि के रूप में जिस पर विश्राम किया जा सकता है, अनुमति नहीं दी जाएगी और/या पूंजी राशि से बाहर रखा जाएगा और इसे केवल ब्याज के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

(8) अल्पावधि और डिक्री के मुकदमेबाजी का इंतजार का अधिनिर्णय अदालत के साथ विवेकाधीन है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से खंड 34 सी.

पी. सी. द्वारा शासित होता है जो पक्षों के बीच अनुबंध को अस्वीकार करता है। किसी मामले में यदि अदालत को पता चलता है कि मूल पैरा 8 में)

"8. 'ब्याज' और 'क्षतिपूर्ति' शब्दों का उपयोग कभी- कभी एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और अन्य अवसरों पर उनका अलग अर्थ होता है। 'सामान्य शब्दों में 'ब्याज' एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से संबंधित या बकाया राशि के उपयोग या प्रतिधारण के लिए वापसी या क्षतिपूर्ति है। अपने संकीर्ण अर्थों में, 'ब्याज' का अर्थ उस राशि से समझा जाता है जिसे किसी ने उधार लिए गए धन के उपयोग के लिए भुगतान करने का अनुबंध किया है। किसी विशेष मामले में 'ब्याज' को किसी भी श्रेणी में रखा जाए, यह धन के उपयोग के लिए या इसकी मांग में सहनशीलता के लिए भुगतान किया जाने वाला एक प्रतिफल है, जब यह देय हो जाता है, और इस प्रकार, यह धन के उपयोग या सहनशीलता के लिए एक शुल्क है। इस अर्थ में, यह कानून द्वारा अनुमत या पक्षों द्वारा निर्धारित, या प्रथा या उपयोग द्वारा अनुमत, धन के उपयोग के लिए, दूसरे से संबंधित, या भुगतान योग्य होने के बाद धन का भुगतान करने में देरी के लिए एक मुआवजा है।

यह पंजाब उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ अपील है जिसे डॉ. शाम लाल नरूला मामले में उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

38. हालांकि "दंडात्मक ब्याज" को "ब्याज" से अलग करना होगा। दंडात्मक ब्याज एक असाधारण दायित्व है जो एक देनदार द्वारा गलत व्यक्ति होने के कारण किया जाता है, जिसने गलत व्यक्ति के पक्ष में भुगतान नहीं करने की गलती की है और यह न तो नुकसान से संबंधित है और न ही सीमित है। इस प्रकार, जबकि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व मुआवजे के सिद्धांत पर आधारित है, दंडात्मक ब्याज दंडात्मक कार्रवाई के सिद्धांत पर आधारित एक दंड है। दंडात्मक ब्याज चूक की एक अवधि के लिए केवल एक बार लिया जा सकता है और इसलिए इसे पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

39. सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला (1995 संस्करण) ए खंड 34 सी. पी. सी. में बताए गए हितों के तीन विभाजन निर्धारित करता है। विभाजन उस अवधि के अनुसार होता है जिसके लिए न्यायालय द्वारा ब्याज की अनुमति दी जाती है, अर्थात्- (1) निर्णय की गई मूल राशि पर मुकदमा की स्थापना से पहले उपार्जित ब्याज; (2) निर्णय की गई मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज, मुकदमा की तारीख से डिक्री की तारीख तक, ऐसी दर पर जो न्यायालय उचित समझता है; (3) निर्णय की गई मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज, डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक या ऐसी पूर्व तिथि तक जो न्यायालय उचित समझता है, प्रति वर्ष 6 प्रतिशत से अधिक की दर से। लोकप्रिय रूप से तीन हितों को पूर्व- मुकदमा मुकदमेबाजी का इंतजार राशि और ब्याज पोस्ट- डिक्री या भविष्य का

ब्याज कहा जाता है। मुकदमे की स्थापना से पहले की अवधि मुकदमेबाजी का इंतजार प्रक्रिया का विषय नहीं है; ब्याज विचाराधीन कुछ भी मूल कानून का विषय नहीं है (सचिव देखें सिंचाई ओप्ट उड़ीसा सरकार बनाम जी. सी. रॉय एस. सी. सी. पैरा 44- IV)।

अंत में, संविधान पीठ ने कुछ सिद्धांत तैयार किए। वे इस प्रकार हैं:

"(1) यद्यपि ब्याज को इस सादृश्य पर पूंजीकृत किया जा सकता है कि उपार्जित तिथि पर देय ब्याज और बकाया राशि, उस तिथि पर अग्रिम राशि का रूप लेती है, फिर भी दंडात्मक ब्याज, जो भुगतान न करने के लिए दंड के रूप में लिया जाता है, को पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त ब्याज अर्थात ब्याज पर ब्याज, चाहे वह साधारण हो, चक्रवृद्धि हो या दंडात्मक, दंडात्मक ब्याज की राशि पर दावा नहीं किया जा सकता है। दंडात्मक ब्याज को पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है। यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।

(2) नोवेशन, अर्थात, एक लेनदार के साथ एक नया समझौता करना जो पहले से उधार ली गई मूल राशि का भुगतान करता है और ब्याज के साथ कुल राशि को मूलधन के रूप में मानता है, कोई भी अनुबंध व्यक्त या निहित और खातों की एक स्पष्ट स्वीकृति, पूंजीकरण का सबसे अच्छा प्रमाण है। लेनदार द्वारा अपनाए गए लेखांकन के तरीके में अधिग्रहण और

देनदार के ज्ञान में लाए जाने से ब्याज को मूलधन में परिवर्तित किया जा सकता है। विरोध करने में विफलता केवल स्वीकृति नहीं है।

(3) बैंकिंग अभ्यास की व्यापकता आवधिक विश्राम पर ब्याज और अनुबंधों में उनके पूंजीकरण को शामिल करने के बारे में शर्तों को वैध बनाती है। स्वैच्छिक रूप से किए गए और पक्षों पर बाध्यकारी अनुबंधों में शामिल ऐसी शर्तें ब्याज की वसूली और भुगतान के संबंध में पक्षों के मूल अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करेंगी।

(4) पूँजीकरण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहा, हालांकि वह कर सकता था और इस तरह खुद को एक चूककर्ता बना दिया। उधारकर्ता के खाते में डेबिट की गई राशि को पूंजीकृत रखने के लिए यह प्रतीत होना चाहिए कि उधारकर्ता के पास प्रवेश की तारीख को या डेबिट प्रविष्टि की तारीख से उचित समय या अनुग्रह अवधि के भीतर भुगतान करने का अवसर था या देय राशि और जिससे पूंजीकरण से बचा जा सके। उधारकर्ता के खाते में कोई भी डेबिट प्रविष्टि और दावा किया जाता है कि मूल राशि का समामेलन बनाने के लिए पूंजीकृत किया गया है, अदालत के संतोष के लिए दिखाया जा सकता है कि ऐसी डेबिट प्रविष्टि उधारकर्ता के ध्यान में नहीं लाई गई थी और/या उसके पास पूंजीकरण से पहले भुगतान करने का अवसर नहीं था और इस तरह उसके पूंजीकरण को बाहर रखा गया था।

(5) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35- ए द्वारा प्रदत्त शक्ति कार्य करने का कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का प्रमुख बैंकिंग संस्थान है जिसे बैंकिंग पर पर्यवेक्षी भूमिका सौंपी गई है और मुकदमा की तारीख को बाध्यकारी राशि जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

ब्याज वास्तव में अग्रिम की गई मूल राशि के घटक के साथ असमान है, न्यायालय कम दर पर मुकदमेबाजी का इंतजार और डिक्री के बाद ब्याज देने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है या इस तरह का ब्याज देने से भी इनकार कर सकता है। विवेकाधिकार का प्रयोग निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और कारणों से किया जाएगा न कि मनमाने या काल्पनिक तरीके से।

13. सिंडिकेट बैंक, चेन्नई बनाम में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके। मोहन ब्रदर्स और अन्य, (2004) 10 खंड 549 में यह तर्क दिया गया है कि सी. पी. सी. की खंड 34 (1) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यदि निर्णय की गई राशि के संबंध में देयता वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुई थी, तो ऐसे अतिरिक्त ब्याज की दर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत से अधिक हो सकती है, लेकिन ब्याज की संविदात्मक दर से अधिक नहीं होगी और बैंक अनुबंध के अनुसार ब्याज का दावा करने का हकदार है। यह सच है कि इस निर्णय में, तीन-

न्यायाधीशों की पीठ ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले (उपरोक्त) में निर्णय से पता चलता है कि उस परंतुक का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है जो विशेष रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न ब्याज देने से संबंधित है, इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में निर्णय के विपरीत एक बड़ी पीठ द्वारा हमें किसी भी निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया गया था। अन्यथा, तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए, यहां तक कि कंपनी भी निपटान के लिए सहमत हो गई, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों और अन्य सभी परिस्थितियों के कारण यह सफल नहीं हुआ, हम महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय ने बैंक के दावे के साथ- साथ कंपनी की पीड़ाओं को भी काफी हद तक बेअसर कर दिया है और ब्याज की दर को 14 प्रतिशत प्रति वर्ष तक कम करके एक व्यवहार्य आदेश पारित किया है, जो कि साधारण ब्याज होगा, अवधि के मुकदमेबाजी का इंतजार और भविष्य के ब्याज के संबंध में, जिस दिन बैंक ने डी. आर. टी. के समक्ष आवेदन दायर किया था। हालांकि कंपनी द्वारा 12 प्रतिशत प्रति वर्ष तक की और कटौती के लिए अनुरोध किया गया था, क्योंकि यह एक वाणिज्यिक लेनदेन था और बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के कारण, हम उनके अनुरोध मान लेना करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

14. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम स्वीकार्य है और हम या तो बैंक द्वारा दावा की गई ब्याज दर को बढ़ाने या

कंपनी द्वारा अनुरोध किए जाने पर और कटौती का आदेश देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। नतीजतन, दोनों अपीलों को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

डी जी।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मयंक प्रताप सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।